देश की समृद्धि में जनभाषा में शिक्षा पद्धति

संक्रांत सानु

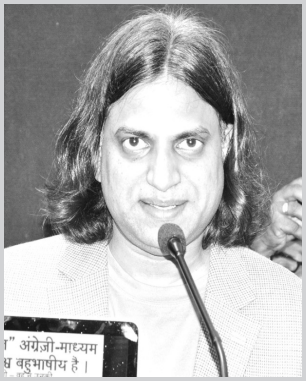

मैंने एक बहुत छोटी-सी स्टडी की। मैंने जीडीपी के आधार पर बीस सबसे समृद्ध देश देखे और जो सबसे छोटे देश थे जिनकी पापुलेशन पांच मिलियन से कम थी, उनको छोड़ दिया। तो जो बीस सबसे समृद्ध देश देखे जीडीपी के आधार पर उनमें मैंने यह पाया कि बीस के बीस देश अपनी जन भाषाओं में अभियांत्रिकी, चिकित्सा शिक्षा आदि उपलब्ध कराते हैं। सबके न्यायालय अपनी भाषाओं के आधार पर चलते हैं। उन बीस में से केवल चार देश ऐसे थे जो अंग्रेजी माध्यम पर आधारित थे।

आपको थोड़ा-सा आश्चर्य लगेगा कि मैं पच्चीस साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और स्वयं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की। आईटी कानपुर से बी. टेक किया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में सालों काम किया। लगभग चार महीने मैं भारत में रहता हूँ। ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक है 'अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल' (लेखक स्वयं) भाषा के भ्रमजाल में मैं भी पड़ा हुआ था तो उस भ्रमजाल से कैसे निकला इसकी थोड़ी-सी कहानी सुनाता हूँ।

माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए मेरी एक टीम जो इजराइल में थी, उसको देखने के लिये मैं इजराइल में आईफा पहुँचा और मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, इजराइल के आफिस में माइक्रोसॉफ्ट का हिब्रू माध्यम में कर रहे थे। तो ये डेवलपमेंट सेंटर था माइक्रोसॉफ्ट का। वहाँ पर जो भी उनका कार्य था, वे पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन करते थे, ई-मेल करते थे, आपस में जो टेक्निकल डिस्कशन करते थे, वे सब के सब हिब्रू माध्यम में होते थे। उनकी डाक्यूमेंटेशन हिब्रू में थी। मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा क्योंकि भारत में पला-बढ़ा मेरी यही मान्यता बन गई थी कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता और खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मेरी उस धारणा को इजरायल में चोट पहुँची।

दूसरा वाकया माइक्रोसोफ्ट में रशियन कम्प्यूटर प्रोग्रामर से संबंधित है। माइक्रोसाफ्ट में मैनेजर होने के नाते हमेशा टेलेंट की खोज रहती थी। रशियन कम्प्यूटर प्रोग्रामर को, जिन्हें बिलकुल भी अंग्रेजी नहीं आती थी, बावजूद मैंने उन्हें ज्वाइन करवाया और बाद में वे हमारे श्रेष्ठ प्रोग्रामर निकले। इस तरह मैं 25 देशों में घूमा ये देखने के लिये कि लोग भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मैंने पाया कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी भाषा को छोड़कर विकसित हुआ हो।

आज तक हमारी भारतीय भाषाओं के बारे में जो चर्चा चलती रही है वह यही कि सांस्कृतिक कारणों से हमें भारतीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। लेकिन हम अगर आर्थिक या व्यावहारिक दृष्टि से देखें तब तो अंग्रेजी ही चलेगी। हम अपने बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा जॉब मल्टीनेशनल कम्पनी में मिलेगा वह अंग्रेजी माध्यम से ही मिलेगा। ये हमारी मान्यताएं बन गई हैं। ये गलत भी नहीं है भारत के लिये। भारत के लिये क्यों गलत नहीं है, क्योंकि भारत में जो मान्यता बनी हुई है वो उसके आधार पर ही कि अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है यहाँ

पर। ये विश्व की वास्तविकता नहीं है। विश्व की वास्तविकता बिलकुल अलग है।

मैंने एक छोटी-सी स्टडी की। जीडीपी के आधार पर बीस सबसे समृद्ध देश देखे और जो सबसे छोटे देश थे जिनकी जनसंख्या पांच मिलियन से कम थी, उनको छोड़ दिया। मैंने यह पाया कि बीस के बीस देश अपनी जन भाषाओं में अभियांत्रिकी, चिकित्सा शिक्षा आदि उपलब्ध कराते हैं। सबके न्यायालय अपनी भाषाओं के आधार पर चलते हैं। उन बीस में से केवल चार देश ऐसे थे जो अंग्रेजी माध्यम पर आधारित थे। इस प्रकार बीस में से सोलह देश जो सबसे समृद्ध देश हैं, वे अपनी भाषाओं पर आधारित उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि प्रदान करते हैं। बीस सबसे गरीब देशों में पाया कि अट्ठारह ऐसे देश हैं जो अपनी जनभाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान न कर किसी औपनिवेशिक भाषा में वो शिक्षा दे रहे थे।

हमने मान लिया है कि अंग्रेजी हमारी आर्थिक प्रगति का माध्यम है, लेकिन असल में अंग्रेजी हमारी दुर्गति का माध्यम है। अंग्रेजी हमारी पिछड़ेपन की भाषा है। जब तक हम अंग्रेजी की गुलामी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे। यूरोप में इंडस्ट्री रिवेल्यूशन हुआ तब बहुत सारे लोग समृद्ध हुए। पहले उनकी उच्च शिक्षा लेटिन में होती थी क्योंकि वहाँ जो विश्वविद्यालय थे उनमें लेटिन माध्यम में ही पढ़ाई होती थी। जब अपनी भाषा, जन भाषा में आए तभी समृद्ध हुए।

अगर कहें कि ठीक है गाने-बजाने के लिये आप हिन्दी प्रयोग कर लो, बंगाली प्रयोग कर लो, लेकिन कल आईटी में जाना है तब तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको मल्टीनेशनल कम्पनी में काम करना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। जब तक धारणा रहेगी कि जो उच्च कोटि का है वह अंग्रेजी माध्यम का होगा और जो निम्न कोटि का है वह भारतीय भाषाओं का होगा। तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती।

पोलैंड मैं अभी हाल ही में गया। वहाँ मेरी बात इंजीनियरिंग स्टूडेंट से हुई। मैंने कहा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन-सी भाषा में पढ़ते हो? उसने बताया- पोलिश में। मैंने कहा आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसने कहा कि नहीं। उसने बताया कि हमारे मूल वैज्ञानिक पोलिश के हैं वे पोलिश में ही पुस्तकें लिखते हैं।

आप जापान जाएं, कोरिया में जाएं, जापान के न्यूरोसर्जन हैं वे सब अपनी भाषा के आधार पर काम कर रहे हैं और एक शोध के आधार पर साइंस में ऐसे किसी व्यक्ति को नोबल पुरस्कार नहीं मिला है जिसने अपनी मातृभाषा में साइंस न पढ़ी हो। अभी कई अध्ययन सामने आए हैं जिसके आधार पर अगर आप विज्ञान अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी विज्ञान की समझ कम है। चाहे आप अंग्रेजी में या किसी और भाषा में पढ़ रहे हों। आंध्रप्रदेश में हुए अध्ययन के आधार पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की विज्ञान की समझ तेलुगू माध्यम में पढ़ रहे विद्यार्थियों से कम थी।

पहली बात तो ये कि आपको अंग्रेजी सीखने का बोझ, फिर विज्ञान सीखने का बोझ। अगर अपनी भाषाओं में पढ़ोगे तो आपको भाषाएं आती हैं। तो उसमें विषय सीखना ज्यादा आसान होता है। लेकिन विडंबना है, हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, हमारी राज्य व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, नीति ऐसी बनी हुई है जिसमें हम अंग्रेजी को 'हाई स्टेटस' मानते हैं और भारतीय भाषाओं को 'लो'। 3-4 प्रतिशत लोग हैं विश्व में जो इंग्लिश को अपनी सैकेंड लैंग्वेज की तरह जानते हैं, जिनकी मूलभाषा अंग्रेजी नहीं है। मूल भाषा अंग्रेजी केवल तीन-चार प्रतिशत लोगों की है। तो देखें मल्टीनेशनल की बात करते हैं। सैमसंग का आप सबने नाम सुना होगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पूरे विश्व में फैली हुई है। हमारी भारतीय कोई कंपनी नहीं है जो इतनी फैली हुई हैं? लेकिन सैमसंग का जो सीईओ है उसने कोरियन में एमबीए किया हुआ है। सैमसंग कंपनी के जो इंजीनियर हैं उन्होंने कोरियन भाषा में ही इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो हमारी मान्यता है जो कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, केवल हमारी ही मान्यता है। इसका मूल कारण भारत सरकार की नीति है, जिसने अंग्रेजी को ऊपर रखा है। जैसे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में

किसी भारतीय भाषाओं में वकालत नहीं कर सकते। आपको केवल अंग्रेजी में करनी पड़ेगी।

बार-बार हम बता रहे हैं अपने नागरिकों को कि जो भारतीय भाषाएँ हैं वह नीचे हैं अगर लोअर कोर्ट में प्रेक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो भारतीय भाषाओं में। उच्चकोर्ट में करनी है तो ऊपर अंग्रेजी बैठी हुई है। दो-चार को छोड़कर, बाकी हाईकोर्ट में भी अंग्रेजी चलती है। ये राज्य की तरफ से हमें बार-बार मैसेज मिल रहा है कि अंग्रेजी ऊपर और भारतीय भाषा नीचे है। हमें यह कहने में दुःख हो रहा है कि अभी पीआईएल आया था सुप्रीम कोर्ट में ताकि सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी चले लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया।

मैं अभी तुर्की में था और तुर्की वाले अपने देश को तुर्की बुलाते हैं, टर्की तो अंग्रेजी से सीखा है। वहाँ जब मैं किसी से बात कर रहा था भाषा की, तो उन्होंने कहा कि- अंग्रेजी यहाँ भी थोड़ी बहुत चल रही है। लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिसिन सब आप टर्की में कर सकते हो। जब मैंने बताया कि हमारे जो न्यायालय हैं वो अंग्रेजी में चलते हैं तो वे चौंक गये कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि न्यायालय में क्या हो रहा है।

आईटी में, आईआईएम में, बिजनेस स्कूल में आप पढ़ ही नहीं सकते। इम्तहान आपको अंग्रेजी में देने पड़ेगे। ऐसे ही अगर आपको आर्मी में जाना है तो अफसर बनने के लिये आपको अंग्रेजी में परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर जवान बनना है तो किसी भी भारतीय भाषा में परीक्षा दे सकते हो। तो हर स्तर पर हम लोगों से यह कह रहे हैं कि तुम नीचे हो, तुम्हारी भाषाएं नीची हैं और अगर ऊपर जाना है तो गुलामी सीखो, यह व्यवस्था बदलनी बहुत आवश्यक है।

अभी मैं दस दिन चीन में रहकर से आया हूँ। चीन में एयरपोर्ट पर ऑडी कार का विज्ञापन चीनी में देखा। मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मुझे हिन्दी का नामो निशान नहीं दिखता कहीं पर। मैं बीजिंग के अंदर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गया। वे यूनिफार्म वगैरह पहने हुए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था पूरे रेस्टोरेंट में। आपको एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं आता तो कोई बात नहीं, उनके पास आईफोन सिक्स है। अपनी भाषा में हमारी बात कम्युनिकेट करने के लिये। चीनी भाषा में अपना आईफोन सिक्स उन्होंने बना डाला। उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद दिखाया। टैक्सी ड्रायवर भी बीजिंग में आईफोन सिक्स लेकर घूम रहा है। जहाँ भी जाना हो और चीनी जीपीएस के सहारे ले जाता है, हमने भारत में अंग्रेजी को तकनीकी शिक्षा के लिये मान लिया है इसलिये एक वर्ग तक ही हमारी तकनीकी शिक्षा सीमित रह गई है। हमारे यहाँ टैक्सी ड्रायवर आईफोन लेकर नहीं घूम रहा है टैक्सी में।

एक बार मैं आईक्यू टेस्ट लेने के लिये गाँव में घूमा। मैं अमेरिका से आईक्यू टेस्ट लेकर आया (इसमें भाषा का कोई उपयोग नहीं था)। उसको लेकर मैं हरियाणा, उत्तराखंड राजस्थान के गाँव में घूमा और बच्चों का आईक्यू टेस्ट लिया। मैं इसलिये आया था कि मेरी मान्यता थी कि भारत के गाँव में भी टेलेंट है। उसको ढूँढ़ने निकला था। मैंने आईक्यू टेस्ट अपनी बिटिया के स्कूल में अमेरिका में दिये, जयपुर में कुछ शहरी बच्चों को दिये और फिर गाँव के बच्चों को दिये और आपको आश्चर्य होगा कि जो मेरे टेस्ट थे उसमें जो गांव का बच्चा था वह आईक्यू में भारत के शहरी बच्चे और विदेश के बच्चे से आगे निकला।

हरियाणा के पास एक गाँव है, मैंने वहाँ प्राध्यापकों से पूछा कि ये बच्चे क्या करते हैं। बच्चों का आगे का क्या फ्यूचर है। उस गाँव के बच्चों में तीस प्रतिशत बच्चे 90 प्रतिशत तक आगे थे आईक्यू टेस्ट में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। उन्होंने बताया कि जब आठवीं कक्षा में बच्चा जाता है उसमें एक हीनता की भावना आ जाती है। उसको लगता है कि आगे की सारी शिक्षा अंग्रेजी में है। अभी बच्चा पढ़ने में तेज है लेकिन इसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। बड़ी विडंबना है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमें स्किल ट्रेनिंग करनी है, रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है, जब तक तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में नहीं लाओगे तो स्किल डेवलपमेंट कैसे करोगे। कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करोगे।

गाँव का बच्चा सोचता है वह पीएच.डी. नहीं कर

सकता है, न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है। उसको कोई बात नजर नहीं आती। उसको लगता है कि यह पहाड़ समान अंग्रेजी उसके ऊपर हावी है। अंग्रेजी की जो क्लास है उसको कैसे तोड़कर वह आगे जायेगा। हो सकता है बच्चा विज्ञान में बड़ा होशियार हो, गणित में बड़ा होशियार हो, लेकिन भाषा में न हो। अलग-अलग टैलेंट होते हैं लोगों के। किसी के लिये अंग्रेजी आसान है, किसी के लिये कठिन है। मैंने किसी देश में ऐसा नहीं पाया कि कोई अपनी भाषाओं को मारने में तुला हुआ हो।

आपको मैं थाइलैंड का किस्सा सुनाता हूँ। चाईना के बाद मैं थाई प्रदेश में गया। हम उसे थाइलैंड बुलाते हैं, लेकिन वो अपने देश को थाई प्रत्योर बुलाते हैं। प्रदेश से ही शब्द निकला है क्योंकि उनकी पूरी भाषा संस्कृत आधारित है। उनकी विज्ञान शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ सबके सब अपनी थाई भाषा में होते हैं।

जैसे ही हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे हमारी तो इतनी भाषायें हैं, कैसे हम आपस में बातचीत करेंगे? पहली बात तो यह पूछना कि जब अंग्रेजी नहीं थी तब आपस में हम बातचीत नहीं करते थे क्या? एक छोटा-सा बच्चा केरला से आदि शंकराचार्य नाम का चला और पूरे देश में गया। उसने मठ स्थापित किये। वह बिना भाषा जाने कहीं सोये होंगे, खाया होगा, बातचीत की होगी।

आपस में भारतीय भाषाओं को सीखना भी बहुत कठिन नहीं है, एक भाषा से दूसरी भाषा। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी के बिना आपस में बातचीत नहीं कर सकते। दूसरी कि इतनी सारी भाषाएं हैं? भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। यूरोपियन यूनियन में 24 ऑफिशियल भाषायें हैं और यूरोपियन यूनियन आफिस, 24 की 24 भाषाओं को आफिशियल मानता है। आप किसी भी 24 भाषाओं में पत्र लिख सकते हैं और आपको उसी भाषा में उसका उत्तर मिलेगा।

यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर जाइये तो 24 भाषाओं में उनकी वेबसाइट उपलब्ध हैं। उसमें क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं है। जो राज्य है उसको नागरिकों को सुविधा देनी है। यह नागरिक राज्य के हिसाब से देश की सुविधाएँ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुवादक बैठा दीजिये। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिये नहीं चलते, ये लोगों के लिये चलते हैं। यूरोपियन यूनियन की कुल जनसंख्या भारत की तीन-चौथाई है। पूरे देशों को मिला लिया जाए तो यूरोपियन यूनियन के तो उसकी कुल जनसंख्या भारत की तीन चौथाई है। आपको कांटीनेंट की तरह सोचना पड़ेगा। यह देश नहीं है कांटीनेंट है। इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है।

भाषा नीति का सार बहुत ही सरल है कि हर बच्चा अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा पा सके। राज्य का दायित्व है कि यह सुविधा उसको प्रदान करे। अपनी भाषा में वह जहाँ तक पढ़ना चाहे, चाहे वह तमिल में, चाहे कन्नड़ में, चाहे बंगाली में, चाहे वह हिन्दी में पढ़ना चाहे। एक कॉमन संस्कृत वोक्युबलरी, टेक्निकल वोक्युबलरी बना सकते हैं ताकि परस्पर उनका संवाद बना रहे।

अगर आप यूरोप में भी देखिये तो छोटे-छोटे देश हैं, चेक रिपब्लिक, स्टोनिया, बहुत छोटे देश अपनी भाषाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निकल वोक्युबलरी है वह ग्रीक से निकली हुई है। दो डॉक्टर आपस में बातचीत कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल वोक्युबलरी है वह ग्रीक से निकली हुई है। इसलिये टेक्निकल वोक्युबलरी संस्कृत के आधार पर बना सकते हैं।

कम्प्यूटर में अब ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की सुविधा बहुत बढ़ गई है। मेरे आईटी कानपुर में एक प्रोफेसर होते थे, वो अब आईआईटी वाराणसी के डायरेक्टर हैं, आईआईटी बीएचयू में उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का सॉफ्टवेयर 25 साल पहले शुरू किया था। ट्रांसलेट के लिये उन्होंने जो मशीन उपयोग की है, वह संस्कृत पर आधारित है। उन्होंने संस्कृत का आधार लेकर परस्पर अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया है और अब मजेदार बात ये है कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन 95 प्रतिशत तक सही हो गया है भारतीय भाषाओं का। भारतीय भाषाओं का ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन से 95 प्रतिशत तक हायर किया जा सकता है कम्प्यूटर से।

लेकिन अगर अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद

करना चाहें या भारतीय भाषा से केवल अंग्रेजी में करना चाहें तो यह केवल 60 प्रतिशत है।

अगली बात मैं करूँगा प्रोडक्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनी की। चीन में हाल ही में वॉलमार्ट को फाइन किया गया था? वॉलमार्ट कंपनी बहुत बड़ी रीटेल कंपनी है। वह मल्टीनेशनल के साथ सामान बेचती है। क्यों फाइन लगाया गया? क्योंकि वे एक प्रोडक्ट बेच रहे थे जिस पर अंग्रेजी भाषा का लेबल था वह चीनी भाषा से थोड़ा-सा बड़ा था। इसलिये वॉलमार्ट के ऊपर फाइन लग गया। लेकिन भारत में देखता हूँ यहाँ पर भारतीय भाषाओं का लेबल ही नहीं दिखता। चीन में पूरे विश्व में से कोई चीनी भाषा पढ़ें तो उसको स्कालरशिप दी जाएगी और भारत में अंग्रेजी लगातार बढ़ती जा रही है, अनायास ही नहीं। ये इनका षड्यंत्र है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का।

ब्रिटिश काउंसिल स्टडी करती है कि कितनी पेनेट्रेशन होगी अंग्रेजी की, उसको कैसे बढ़ायें। फोर्ड फाउंडेशन इसके पीछे लगी हुई है तो ये ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिल रहा है। ये उनका षड्यंत्र है और हम मूर्खों की तरह उसको अपनाये जा रहे हैं। यह बदलना होगा।

(लेखक, भाषा विज्ञानी एवं माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं।)